eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के उपायों का अध्ययन

डॉ0 अशोक कुमार[1]
[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र, डॉ0 राममनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज, जौनपुर, उ0प्र0

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

वर्ष 1991 से शुरू किये गये आर्थिक सुधारों के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रबल एवं सतत आर्थिक वृद्धि की है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कारण आये आर्थिक संकट से उबरते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनः गति पकड़ ली है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत की विकास दर को 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसी तीव्र आर्थिक वृद्धि का परिणाम ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ती हुई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब हमारा लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाते हुए विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कारगर एवं प्रभावी रणनीतियां बनानी होंगी।

इसके लिए एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश की भी आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने 2019 में ही 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने हेतु रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया था। परन्तु कोरोना महामारी के कारण इन रणनीतियों को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। परन्तु 2022–23 के उच्च संवृद्धि दर ने 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को साधे जाने की संभावना को पुनः जीवंत कर दिया है।

कीवर्ड– भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन डॉलर, सतत आर्थिक वृद्धि, उच्च संवृद्धि

Introduction

वर्ष 2018 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये 'विजन ऑफ ए यू0एस0 डॉलर 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी' में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से 1 ट्रिलियन डॉलर, विनिर्माण क्षेत्र से 1 ट्रिलियन डॉलर तथा सेवा क्षेत्र से 3 ट्रिलियन डॉलर प्राप्त करते हुए 5 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गयी थी। इसके तहत 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु कोरोना महामारी के वैश्विक संकट ने इन सम्भावनाओं को वास्तविकता में परिणत नहीं होने दिया। कोरोना महामारी एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत की विकास दर में 6.6 प्रतिशत का संकुचन हुआ था यानि कि विकास दर ऋणात्मक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 9.1 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल की गयी परन्तु यह 2020–21 के निम्न विकास दर वाले आधार वर्ष का परिणाम थी। वर्ष 2022–23 में 7.2 प्रतिशत की स्वस्थ विकास दर हासिल की गयी। वर्ष 2022–23 में एक उच्च विकास दर प्राप्त करने के बाद भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के स्वप्न में फिर पंख लगे और भारत सरकार के वित्त विभाग की तरफ से 'रोडमैप फॉर मेकिंग इंडिया ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी' जारी किया गया। इसके तहत समष्टि स्तर के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना और इसे सूक्ष्म स्तर पर सर्व–समावेशी कल्याण के साथ समेकित करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिन टेक

©IJARPS JOURNAL, 2024

को बढ़ावा देना, तकनीकि समर्थित विकास पर बल देना, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु संबंधी कार्यवाही के साथ निवेश एवं संवृद्धि के एक सद्गुण चक्र पर भरोसा करना शामिल हैं। वस्तु एवं सेवाकर (GST) संबंधी सुधार, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (IBC-Insolvency and Bankruptcy Code) सुधार, मेक इन इंडिया और स्टार्ट–अप जैसी रणनीतियां और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के बल पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

समावेशी–विकास के लाभ अर्थव्यवस्था के सभी स्टेकहोल्डर्स विशेषकर वंचित तबके तह पहुँचाना।

डिजिटल अर्थव्यवस्था–ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लेन–देन/खरीदने–बेचने की गतिविधियों का डिजिटलीकरण हो जाय

फिनटेक–व्यक्तिओं और कंपनियों को प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं की तकनीकि

स्टार्ट अप–यह किसी कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। यह एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो ऐसे उत्पाद या सेवा विकसित करना चाहते हैं जिनके लिए बाजार में मांग है।

सब्सिडी–यह एक वित्तीय लाभ या सहायता है जो आमतौर पर सरकार द्वारा संस्थाओं या व्यक्तिओं को दी जाती है। इसका उद्येश्य सरकार सरकार की आर्थिक एंव सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देना है।

माइक्रो इरीगेशन–इस सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों के नेटवर्क का उपयोग करके पानी की पूर्व निर्धारित मात्रा को फसल तक पहुँचाया जाता है। इससे एक ओर पानी के अपव्यय को रोकने में मदद मिलती है वहीं दूसरी ओर यह जल उपयोग की दक्षता को भी बढ़ाता है।

होम स्टेज–यह पर्यटकों के लिए रूकने की एक सुविधा का नाम है जहाँ पर पर्यटक किसी ऐसे स्थानीय व्यक्ति के घर रूकते हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए अपने घर पर रूकने, खाने और यहाँ तक कि कुछ मामलों में यात्रा की भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

मुद्रा लोन–प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम रूपये 10 लाख तक की लोन राशि प्रदान की जाती है। इस लोन के लिए आवेदक को बैंकों या लोन देने वाली संस्थाओं को कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इसका भुगतान 5 वर्ष में करना होता है।

$5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भारत निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करेगा–

1. कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका–$5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषकों एवं गाँवों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी तक हमने अपने किसानों को केवल अन्नदाता के रूप में देखा है, अब हम उन्हें निर्यातक के रूप में देखेंगे। चाहे खाद्यान्न हों, सब्जियाँ हों, फल हों या फिर शहद, निर्यातक के रूप में अपार संभावनाएं हैं। किसान जो कुछ भी पैदा करता है सरकार उसमें वैल्यू एडिसन करके निर्यातों को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही भारतीय किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाकर भी उनकी आय में वृद्धि की जायेगी। किसान अपनी फसल भूमि पर ही सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और अपने उपयोग से अतिरिक्त ऊर्जा को बेच भी सकेंगे। 'प्रधानमंत्री मत्स्स सम्पदा योजना' के तहत मछली पालन और मछली पकड़ने के लिए सरकार मछुआरों को सहायता उपलब्ध करायेगी और साथ ही मछुआरों द्वारा

पकड़ी गयी मछली के भी भंडारण की सुविधा उपलब्ध करायेगी जिससे इसके द्वारा अधिकतम सम्भावित लाभ मछुआरों को प्राप्त हो सकें।

वर्तमान सरकार ने किसानों को उच्च प्राथमिकता पर रखा है। पहले की सरकारों द्वारा केवल कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर ही बल दिया जाता था। परंतु वर्तमान सरकार ने कृषि को उत्पादकता के साथ ही लाभ से भी जोड़ा है। वर्तमान सरकार कृषकों की आय को बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। न्युनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुने की वृद्धि तथा सरकार द्वारा अनाज की भारी खरीद के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के फलस्वरूप किसानों में सुरक्षा का एक भाव जाग्रत हुआ है। 'प्रधानमंत्री किसान योजना' की शुरूआत करके वर्तमान सरकार ने किसानों को सीधे आय प्रदान कर उन्हें सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खातों में सीधे रू06000 की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस सहायता के द्वारा किसान अपनी कृषि संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बने हैं। सरकार द्वारा इस धनराशि को DBT स्कीम के तहत सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार कृषि संबंधी उपकरणों पर और कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी को भी किसानों के खातों में डिजिटल माध्यम से भेजा जा रहा है। मंडियों में किसानों द्वारा बेची गयी उपज के बदले प्राप्त धनराशि भी मंडी द्वारा डिजिटल माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा e-NAM प्लेटफार्म विकसित कर राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की गई है जिसमें 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 585 डिजिटल बाजारों की स्थापना की गई है।

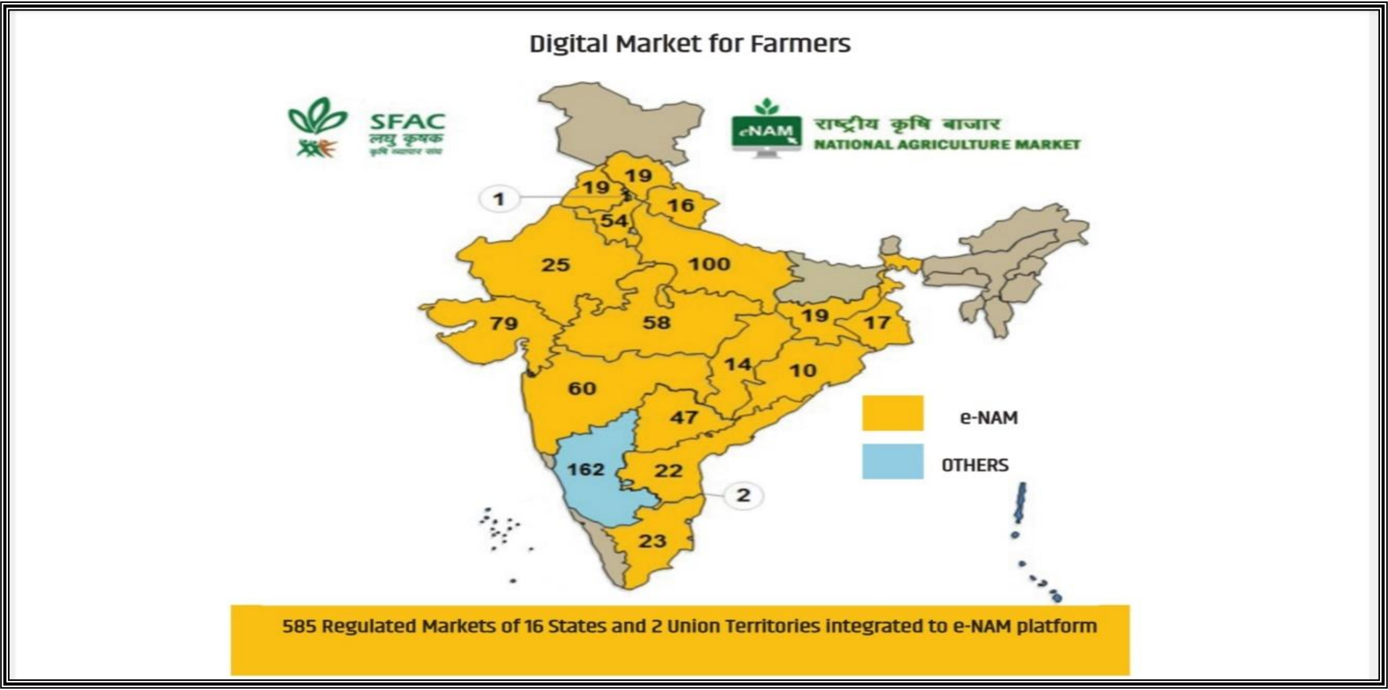

कृषि में उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग, लागतों में कमी और कम पानी खपत करने वाली फसलों की ओर झुकाव के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि निश्चित है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की

अवस्थापना विकास के लिए 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश करने के लक्ष्य के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान हेतु तैयार होगा। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति तैयार करने के लिए सरकार ने 75 हजार युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है जिससे कृषि प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार संभावनाओं के बढ़ने की पर्याप्त संभावना है।

इसी प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के 10,000 नये उत्पादक संगठनों के गठन का निर्णय लिया है जिससे किसानों की बाजारों तक पहुँच आसान होगी और उन्हें अपने उत्पाद का अधिकतम फल प्राप्त हो सकेगा।

पानी का अपव्यय और गलत तरीके से प्रयोग वर्तमान की बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए सरकार माइक्रो–इरीगेशन पर अधिक बल दे रही है। शहरों में अप्रयुक्त पानी की रिसाइक्लिंग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे इसे सिंचाई जैसे अन्य उपयोग में भी प्रयोग किया जा सके। सभी घरों में पानी पहुँचाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी घरों को जल सम्पन्न बनानें के लिए भारत सरकार द्वारा 'जल शक्ति' मंत्रालय की स्थापना की गई है। इसी दिशा में एक जल शक्ति अभियान भी चालू किया गया है जिसके द्वारा हमारी माताएं और बेटियां जो कि सर्वाधिक दुश्वारियां झेलती हैं, उन्हें भी व्यापक रूप से लाभ पहुँचेगा।

2. स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत–$5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक घर में सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर बीमारियों को पनपने की दर में कमी आई है जो कि स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्ययों को कम करने के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के फलस्वरूप देश में स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के फलस्वरूप देश में स्वच्छता कवरेज में हुए सुधार को नीचे दिये गये रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 2014–15 के बाद से हुए प्रयासों के फलस्वरूप देश में स्वच्छता कवरेज बहुत तेजी से बढ़ा है।

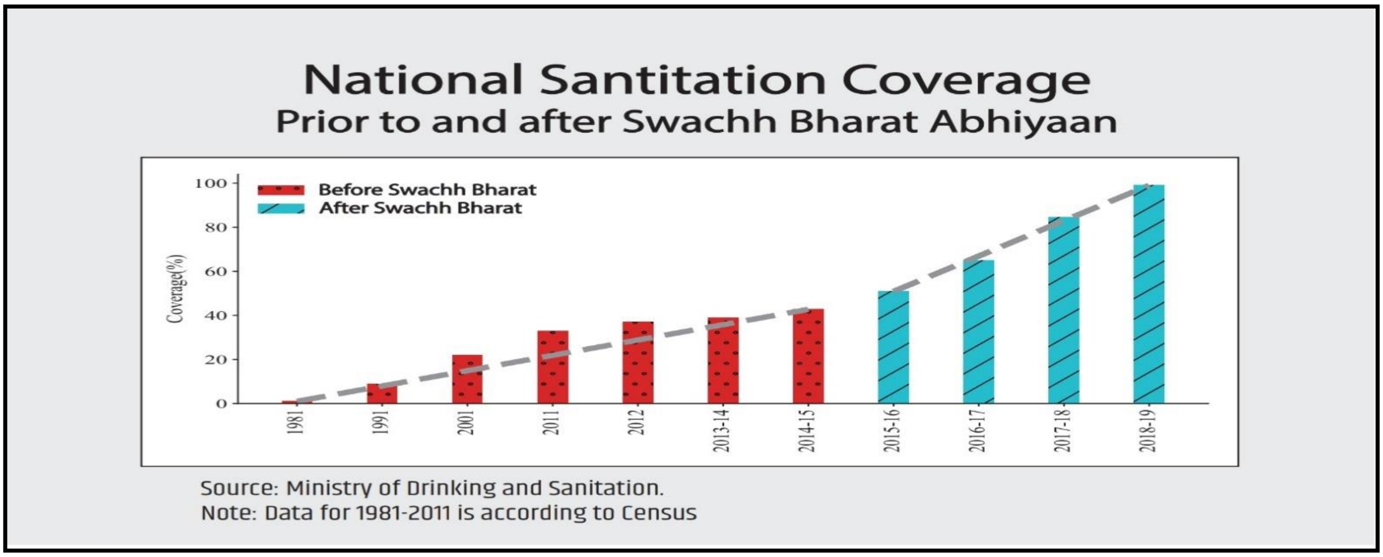

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार स्वच्छता कवरेज में सुधार के साथ डायरिया एवं डिहाड्रेशन से मरने वाले बच्चों की मृत्यु में भी उल्लेखनीय कमी आयी है।

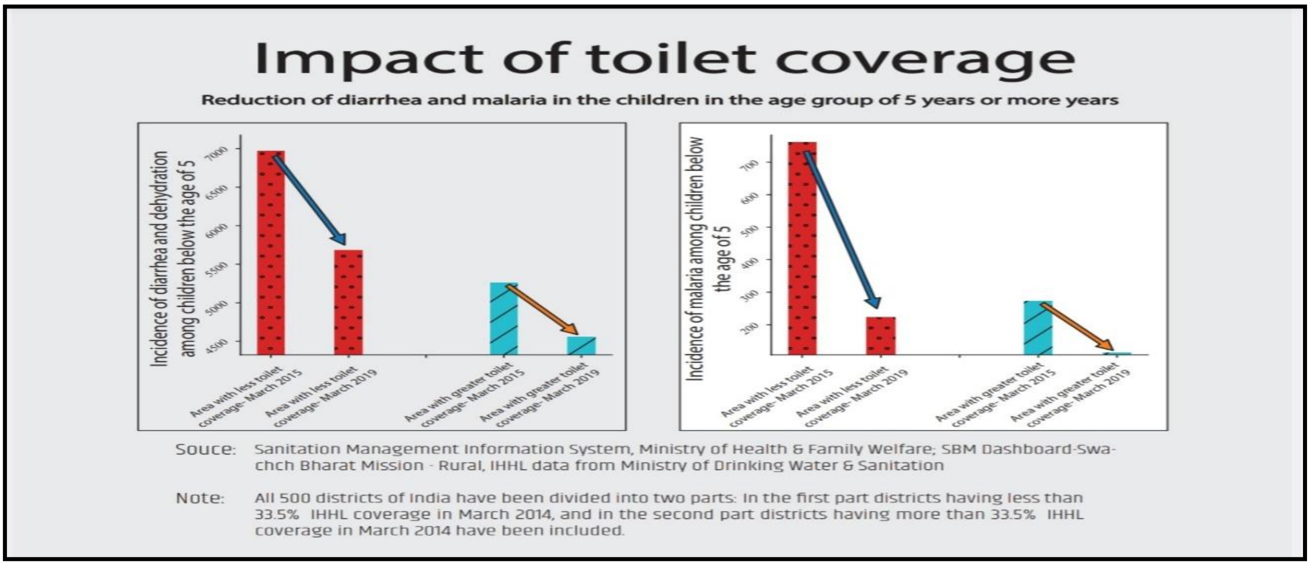

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना अत्यधिक कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत 50 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान किया जा रहा है। नवम्बर 2023 तक इस योजना का लाभ 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों तक पहुँच चुका है। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के इलाज के लिए फंड सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्वस्थ भारतीय नागरिक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अधिक योगदान देने में निश्चित रूप से अधिक सक्षम होंगे।

3. पर्यटन समृद्धि के नये द्वार खोलेगा—देश के सुंदर होने पर और उस तक पहुँचने के मार्गों के निर्विघ्न होने पर पर्यटन का बढ़ना तय है। पर्यटन में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किये गये निवेश पर उच्च प्रतिफल प्राप्त होने की सम्भावना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ 'होम स्टेज' का चलन बढ़ा है जो कि लोगों की आय का नया स्रोत बन गयी है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

4. अवस्थापना : नये भारत के लिए एक मजबूत आधार—विकास की गति को केवल अच्छी अवस्थापना सुविधाओं द्वारा ही तेज किया जा सकता है। Highway-Iway कार्यक्रम के माध्यम से सभी गाँवों को ब्राडबैन्ड सुविधाओं द्वारा जोड़ा जायेगा। इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है। गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए 1,50,000 किमी0 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने के लिए 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली—मुंबई एक्सप्रेसवे, रायपुर—विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे, चेन्नई—बैंगलोर एक्सप्रेसवे, दिल्ली—अमृतसर—कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद—धोलेरा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई—नागपुर एक्सप्रेसवे, पटना—पूर्निया एक्सप्रेसवे,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे, वोधगया–राजगीर–वैशाली–दरभंगा एक्सप्रेसवे आदि से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने वाली है।

5. स्टार्ट अप एवं MSMEs–नई अर्थव्यवस्था की तेज धार–आर्थिक क्रियाओं में तेजी आने के साथ आने–जाने के लिए वाहनों की मांग में तीव्र वृद्धि होने वाली है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से कुशल मानव शक्ति तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इससे अर्थव्यस्था के विकास को गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। घरेलू स्टार्टअप को पूंजी सुविधा प्रदान करने के लिए 2016 में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रूपये के आवंटन द्वारा Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Fund of Funds की स्थापना की है।

मध्यम, छोटे और लघु उद्योग छोटे उद्योगपतियों को न केवल अच्छा मुनाफा देते हैं बल्कि यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। कृषि के बाद यही वह क्षेत्र है जहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी लगी हुई। वर्तमान सरकार MSMEs पर इस प्रकार ध्यान दे रही है कि उन्हें सभी बाजार जनित उच्चावचनों से बचाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। MSMEs को आसान ऋण उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्थ में रोजगार संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इनको मुद्रा लोन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। MSMEs सेक्टर को गति देने के लिए वर्ष 2018 के बजट में इस सेक्टर के लिए 12 सूत्री उपाय लागू किये गये हैं। 12 सूत्री उपाय इस प्रकार हैं–1. इसके तहत MSMEs को त्वरित गति से ऋण प्रदान करने के लिए '59 मिनट' लोन पोर्टल को लांच किया गया है। 2. इसी प्रकार इस सेक्टर के लिए दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को बाजार दर से 2 प्रतिशत कम रखा गया है। 3. MSMEs के लिए नकद प्रवाह को आसान बनाने के लिए 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को TReDS पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे वे अपने बिलों मे छूट पा सकें। 4. साथ ही निर्यात करने वाले MSMEs को उनके ऋणों पर 3 से 5 प्रतिशत की रियायत देने का प्राविधान किया गया है। 5. सभी सरकारी मंत्रालयों और संस्थानों को अपनी कुल खरीद का 25 प्रतिशत MSMEs से करना होगा। 6. इसी प्रकार सभी सरकारी विभागों के लिए यह भी तय किया गया है कि वे अपनी खरीद का 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs से खरीदेंगे। 7. मध्यस्थों को हटाने और MSMEs को बाजार की अधिक हिस्सेदारी प्रदान करने के उद्येश्य से यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार के सभी उपक्रम जेम पोर्टल पर मौजूद रहें। 8. MSMEs के तकनीकी उन्नयन के लिए 6000 करोड़ रूपये की लागत से 20 नये केन्द्र और 100 टूल रूम खोले गये हैं। 9. फार्मा कंपनीज को MSME सेक्टर में आने को प्रोत्साहित करने के लिए फार्मा क्लस्टर्स बनाये जायेंगे जिनकी लागत का 70 प्रतिशत तक सरकार द्वार वहन किया जायेगा। 10. MSMEs के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस' को सुनिश्चित करने के लिए रिटर्न वर्ष में केवल एक बार भरा जायेगा। पहले वर्ष में दो बार रिटर्न भरने की जरूरत थी। 11. 'इंस्पेक्टर राज' खत्म

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

करने की दिशा में अब यह पहले से तय किया जा रहा है कि इंस्पेक्टर किन फैक्ट्रीज का निरीक्षण कर सकते हैं। अब इंस्पेक्टरों को कम्प्यूटर के माध्यम से रैण्डम फैक्टरियाँ निरीक्षण हेतु आवंटित की जायेंगी। अब इंस्पेक्टरों को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों में ही कारण सहित प्रस्तुत करनी होती है। 12. पर्यावरण मंजूरी और सहमति को अब साथ में मिलाकर एकल अनुमति में बदल दिया गया है। कंपनीज ऐक्ट के छोटे उल्लंघनों के मामलों में अब MSMEs को न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब एक सरल प्रकिया द्वार इसे सुधारा जा सकता है।

6. अधिक निवेश, अधिक रोजगार, अधिक विकास—भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 55 वर्ष लग गये थे। 2014 से 2019 के बीच बहुत कम समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन और जुड़ गया है। वर्तमान में भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए भारत के GDP को उच्च दर से बढ़ने की जरूरत है। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हमें बचत, निवेश और निर्यात के उच्च स्तरों को प्राप्त करना होगा। नीचे दिये गये विश्व आर्थिक परिदृश्य संवृद्धि अनुमानों से स्पष्ट है कि भारत वर्तमान और आने वाले समय दोनों में विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करने वाला है।

World Economic Outlook Growth Projections

Real GDP, annual % change

Name of the Country/Region	2023	Projections	
		2024	2025
World Output	3.2	3.2	3.2
United States	2.5	2.7	1.9
Euro Area	0.4	0.8	1.5
China	5.2	4.6	4.1
India	7.8	6.8	6.5
Brazil	2.9	2.2	2.1

Source: IMF, World Economic Outlook, April 2024
Note: For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis, with FY 2023/24(starting in April 2023) shown in the 2023 column, India's growth projections are 6.9% in 2024 and 6.5% in 2025 based on calendar year.

ऐसा कर पाने पर ही हम अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए उल्लेखनीय रोजगार उत्पन्न कर पायेंगे। अधिक निवेश विभिन्न आकारों की अनेक स्थानीय कंपनियां उत्पन्न करेगा। इससे हमारी क्षमता का संवर्धन होगा जिससे अनेक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होगी जो कि बदले में पुनः उपभोग

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

को बढ़ायेगा और रोजगार पैदा करेगा। इस निवेश प्रेरित संवृद्धि मॉडल को सफल बनाने के लिए निवेशकों के जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार ने अनेक नयी कर छूटें, नये कानून, निवेश प्रक्रिया का सरलीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश सीमा का विस्तार , श्रम कानूनों का सरलीकरण, रेरा जैसे रियल स्टेट कानूनों का निर्माण करने का उल्लेखनीय कार्य किया है।

7. निवेश को होने देने के लिए नीतियों में स्थिरता–मई 2019 में भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के हाथ में देश की सत्ता सौंपी है। इसके फलस्वरूप निवेश संबंधी नीतियों की निरन्तरता बनाये रखने में मदद मिली है। विश्व के उन देशों में निवेश अधिक होता है जहाँ कानून सरल हैं, सरकारी नीतियों की दिशा स्पष्ट है, तंत्र नियमानुसार चलता है और जहाँ भेदभाव तथा व्यापार संबंधी विवाद बहुत कम होते हैं।

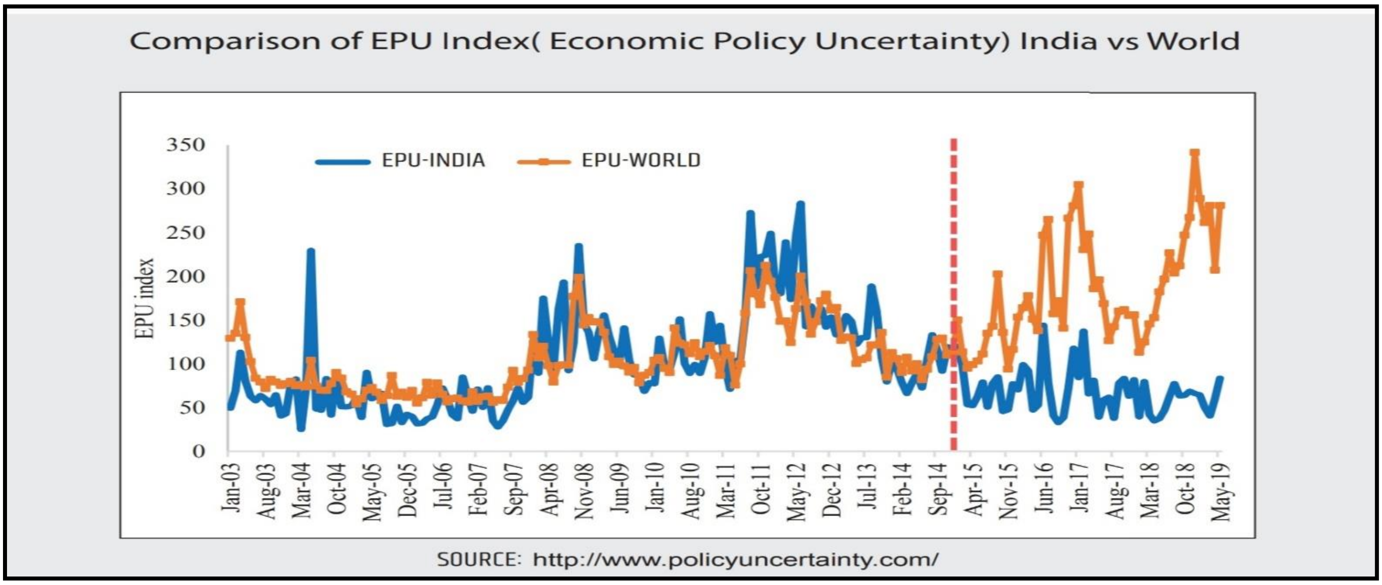

उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 2014 में श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार के गठन के बाद से भारत की आर्थिक नीतियों में लगातार स्थिरता रही है जबकि इसी अवधि में वैश्विक आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता की स्थिति रही है।

8. तकनीकि द्वारा सार्वजनिक कल्याण–JAM Trinity जिसके तहत जन धन–आधार–मोबाइल का समन्वय है, की तकनीकि ने एक कुशल कल्याणकारी राज्य के लिए रास्ता तैयार कर दिया है जहाँ से लाभार्थियों को सही तरीके से पहचाना जा सकता है और उन तक प्रत्यक्ष पहुँच संभव हो सकी है। इस तकनीकि का प्रयोग सरकार और लाभार्थी के बीच अनेक अनावश्यक स्तरों को समाप्त करता है जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लग सका है। इसके फलस्वरूप आभासी और गलत लाभार्थी योजना से बाहर हो रहे हैं और वास्तविक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस तकनीकि के इस्तेमाल ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वास्तविक पहुँच लोगों तक बढ़ाने में मदद की है। तकनीकि के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार दूर होने के सम्बन्ध में लोगों की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है और भविष्य में तकनीकि के और प्रभावी इस्तेमाल को स्वीकार करने

के लिए अब भारत के लोग तैयार हैं। इस प्रकार तकनीकि धन को गलत हाथों में जाने से रोककर देश के लिए ढेर सारे धन की बचत कर रही है।

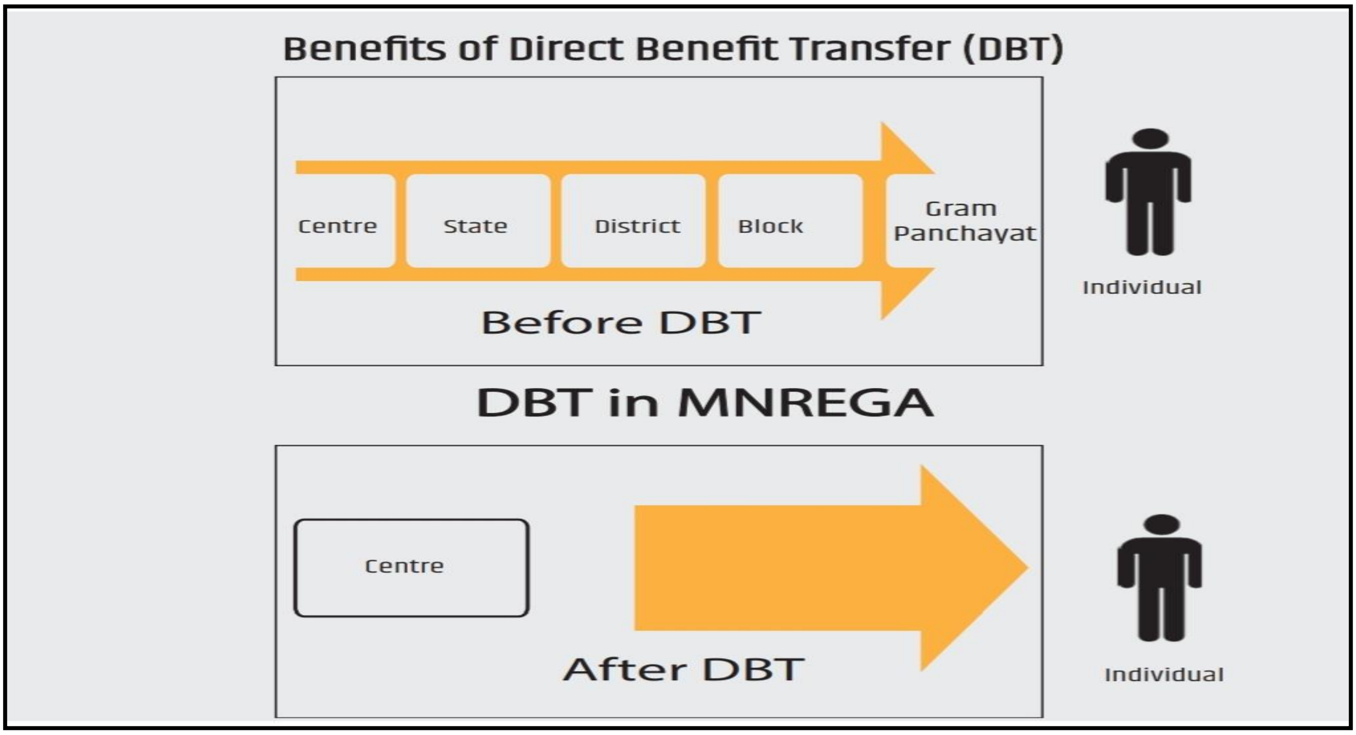

9. नये भारत के लिए नयी ऊर्जा—जिस प्रकार एक वाहन को आगे बढ़ने के लिए ईंधन की जरूरत होती है उसी प्रकार $5 ट्रिलियन वाली विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अपना ऊर्जा उपभोग बढ़ाना होगा और ऊर्जा के सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध स्रोतों को उपयोग करना होगा। सभी गाँवों और लगभग सभी घरों का विद्युतीकरण करके विद्युत की कमी की समस्या को पूरी तरह दूर करने का प्रयास किया गया है। जहाँ किसानों को अच्छी फसल के लिए विद्युत की आवश्यकता है वहीं अच्छी शिक्षा के लिए छात्रों को भी विद्युत की आवश्यकता है। उद्योगों को उनके उत्पादन एवं विस्तार के लिए विद्युत की आवश्यकता है। घरों में लोगों के जीवन को अच्छा बनाने एवं दुनिया तक उनकी पहुँच बनाने वाले उपकरणों को चलाने के लिए भी विद्युत की जरूरत है। विद्युत दूसरे अवसरों में प्रवेश को भी आसान बनाती है। ऊर्जा स्रोतों तक पहुँच के अन्तर्गत स्वच्छ रसोई गैस तक पहुँच को भी शामिल किया जाता है। उज्जवला योजना के प्रारम्भ के साथ करोड़ों महिलाओं को धुएँ से भरे रसाई घर से मुक्ति मिली है और इसका विस्तार लगभग 90 प्रतिशत परिवारों तक हो गया है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पोषणीय ऊर्जा सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊर्जा स्रोतों तक वर्तमान पीढ़ी की पहुँच बढ़ाना। वर्तमान सराकर ने न केवल ऊर्जा के परम्परागत स्रातों की क्षमता में वृद्धि की है अपितु नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी बड़ी वृद्धि की है। हम पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा के मामले में पाँचवे स्थान पर तथा नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में पाँचवे स्थान पर हैं। भारत सरकार द्वारा पोषणीय

ऊर्जा उत्पादन के साथ ही ऊर्जा बचत के लिए आधुनिकतम तकनीकि का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम ने कुल मिलाकर लगभग 50,000 करोड़ रूपये की बचत की है।

भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सोलर पैनल और बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियों को उत्साहवर्धक प्रस्ताव उपलब्ध कराये हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने और सब्सिडी प्रदान करने के लिए अनेक मजबूत कदम उठाये हैं। हमारे मछुआरों को इलेक्ट्रिक सिस्टम से लैस करने के लिए हमारी सरकार ने विशेष उपाय किये हैं। जब यह सभी तंत्र भारत में विकसित किये जायेंगे तो इससे इस क्षेत्र में व्यय में कमी आयेगी। सार्वजनिक व्यय कम होने से पूरी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ होगा। भारत स्वदेशी उपायों से अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करने की आकांक्षा रखता है। सौर ऊर्जा की ही तरह भारत पवन ऊर्जा पर भी जोर देकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इसके अलावा सरकार अपशिष्ट पदार्थों से बिजली बनाने और कृषि अपशिष्ट से बायो फ्यूल बनाने हेतु प्रयासरत है।

तीव्र गति से ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और ऊर्जा बचत यह सभी एक साथ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्वपन को साकार करने में सहायता करेंगे।

वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को वास्तविकता में परिणत करने के लिए बिग–पुश की जरूरत है। एक साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश किये बिना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावनाएं क्षीण ही रहेंगी। हम लगभग दो दशक से अधिक समय से अपनी जनसंख्या के जनांकिकीय लाभों (Demographic Dividend) के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी हम अपने नवयुवकों को आवश्यकता के अनुरूप कौशलयुक्त नहीं बना पाये हैं। कौशल विकास मिशन जैसी योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। एक तरफ हम परम्परागत शिक्षा प्रणाली से भी नहीं हट पा रहे हैं जो कि पढ़े–लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। दूसरी तरफ हम परम्परागत शिक्षा प्रणाली से हटकर कौशल संस्थानों को विकसित करने में हिचकिचा रहे हैं। परम्परागत शिक्षा प्रणाली से न हट पाने की कुछ मजबूरियां अवश्य हैं अतः हमें परम्परागत शिक्षण संस्थानों में ही कौशल विकास प्रणाली को विकसित करना होगा। अभी भी समय है यदि हम अपने जनांकिकीय विशेषता का लाभ उठाने के लिए अपने युवाओं को कौशल युक्त बना पाये तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उससे आगे के भी लक्ष्य प्राप्त करना कोई दुरूह कार्य नहीं होगा। आजादी के बाद देश के विकास पथ पर आगे बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। परन्तु देश के सामाजिक ढांचे और समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक पूर्वाग्रहों के फलस्वरूप अभी भी महिलाओं के रोजगार की स्थिति पुरूषों की अपेक्षा कम है। यदि हम किसी तरीके से महिला कार्यशील जनसंख्या को रोजगार/स्वरोजगार से आच्छादित कर पाये तो देश की GDP बढ़ाने में यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसी प्रकार हम अपने किसानों एवं कृषि को अनिश्चितता से बाहर नहीं निकाल पाये हैं। भारत में कृषि अभी भी मानसून के भरोसे है जिससे इस क्षेत्र में आय की अनिश्चितता बनी रहती है। इस आय की अनिश्चितता को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाकर समाप्त किया जा सकता है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आय असमानता वाले देशों में एक है। भारत की ऊपर की 10 प्रतिशत आबादी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

देश के लगभग 80 प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक है। सबसे धनी 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 53 प्रतिशत सम्पत्ति है। गरीबों में से नीचे के 50 प्रतिशत के पास देश की मात्र 4.1 प्रतिशत सम्पत्ति है। इन आँकड़ों की पुष्टि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट–2022 से भी हो जाती है। वैश्विक स्तर पर देशों की आय–असमानताओं का अध्ययन 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' द्वारा किया जाता है। 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' के आँकडों के आधार पर प्रतिवर्ष वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है।

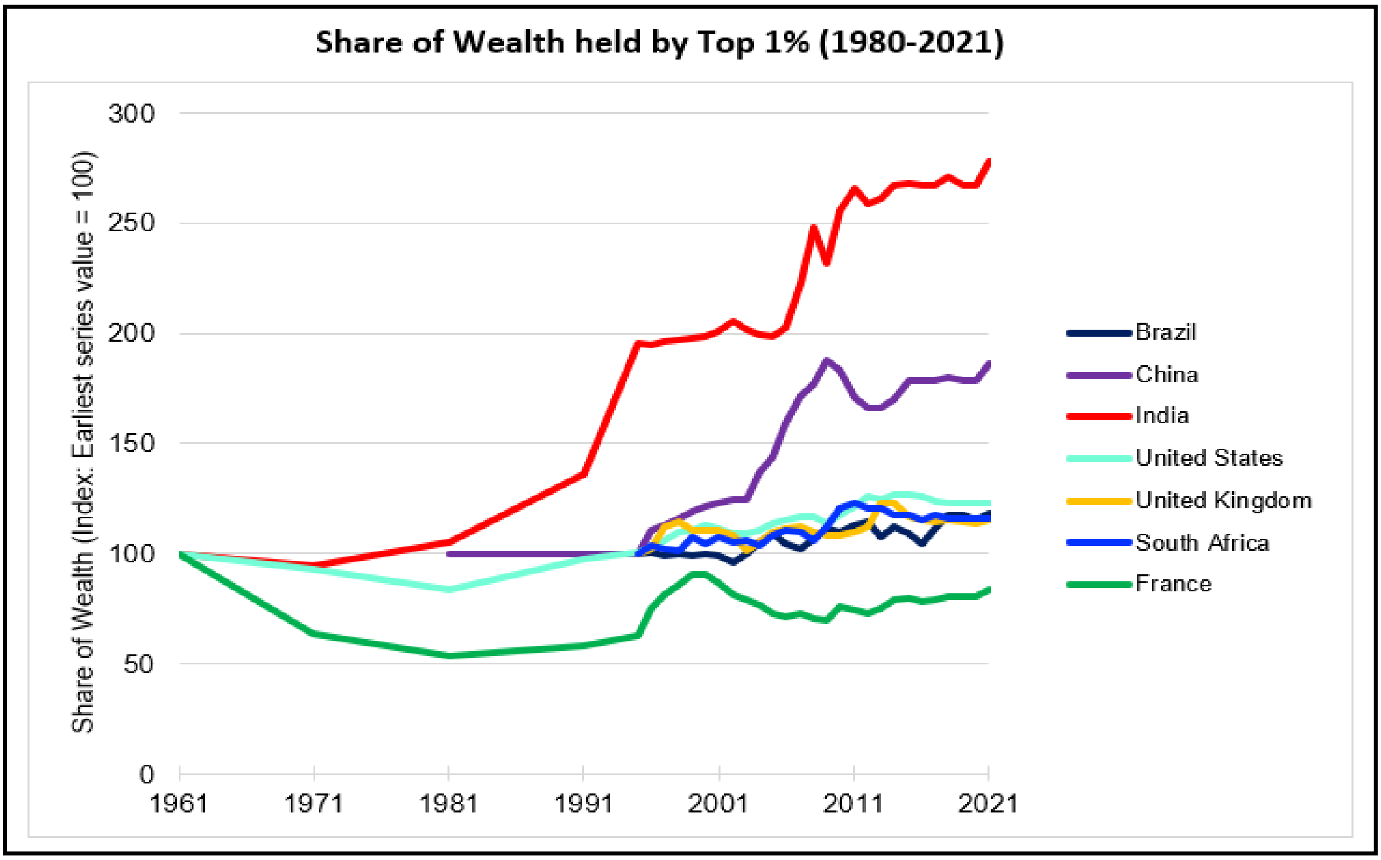

माँग को बनाये रखने के लिए गरीब एवं मध्यम वर्ग के पास पर्याप्त आय का बने रहने आवश्यक है। यदि आय असमानता की यही स्थिति बनी रही तो देश में निवेश को प्रेरित करने हेतु आवश्यक माँग की कमी हो जायेगी और देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावनाएं क्षीण हो जायेंगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बिना सभी वर्गों की भागीदारी के असम्भव होगा। भारत में करारोपण का अधिक भार गरीबों पर है। वस्तु एवं सेवाकर का लगभग 64 प्रतिशत भाग जनसंख्या के सबसे गरीब 50 प्रतिशत लोगों से आ रहा है जबकि उच्च आय वाले 10 प्रतिशत लोगों से इसका मात्र 4 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है। कर का अधिक भार गरीब व्यक्तिओं को और गरीबी में ढकेल रहा है। अतः $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गरीबों के ऊपर से कर भार कम करने की जरूरत है। जाति पर आधारित सामाजिक बहिष्कार ने कुछ निश्चित समूहों और लोगों को हाशिये पर रखकर उनको अवसरों, संसाधनों एवं लाभों से वंचित रखकर देश में असमानता को बढ़ावा दिया है। $5 ट्रिलियन

इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जातिभेद पर प्रहार करना भी जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी पर अत्यधिक बल दिया है। प्रभावी जन भागीदारी के लिए जातिगत विभेद को समाप्त करना अति आवश्यक है।

संदर्भ सूची :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19, वाल्यूम–1 और 2, जुलाई–2019, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली–110001।

2. इंडिया टू सून बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, पी0एम0 मोदी, ऐट ब्रिक्स कॉन्फेरेन्स, 23 अगस्त, 2023, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/india-to-soon-become-5-trillion-economy-says-pm-modi-11240341.html

3. इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्ली इन अमृत काल, पंकज सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनान्स, 04 दिसम्बर, 2023, डेकन हेराल्ड
https://www.deccanherald.com/business/economy/india-to-become-usd-5-trillion-economy-early-in-amrit-kaal-minister-of-state-for-finance-pankaj-chaudhary-2796033#google_vignette

4. ए $5ट्रिलियन इकोनॉमी, बट फॉर हूम, 24 नवम्बर, 2024, द हिन्दू
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-5-trillion-economy-but-for-whom/article67565388.ece

5. ऐंग, हेक्टर गोमेज, ल्यूबेक, थॉमस एडवर्ड, द् रोड टू इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी
https://www.livemint.com/opinion/online-views/the-road-to-india-s-5-trillion-economy-11658994649086.html

6. ठाकुर, अनुराग, मिनिस्टर ऑफ इनफॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, भारत सरकार, इल्लीसिट ट्रेड थ्रेटेन्स इंडियाज क्वेस्ट फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमीः बिजनेस डाइजेस्ट, वाल्यूम–20, इश्यू–7।

7. दास, शशिकान्त, $5 ट्रिलियन इकोनॉमीः ऐस्पिरेशन टू ऐक्शन, जनवरी–2020, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्पीचेज।

8. द् हॉलोनेस ऑफ ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 05 अप्रैल, 2021, द् ट्रिब्यून
https://www.tribuneindia.com/news/comment/the-hollowness-of-a-5-trillion-economy-234672/

9. प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, विजन ऑफ ए यू0एस0डी0 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी, अक्टूबर, 2018, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

10. प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, रोडमैप टू मेकिंग इण्डिया ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगस्त, 2023, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

11. पांडे, अंकित एल0 एवं अड़े, आकाश अरविन्दः ए जर्नी टुवार्ड्स द $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर पैनडेमिक, जुलाई–दिसम्बर 2022, जर्नल ऑफ एप्लायड मैनेजमेन्ट, वॉल्यूम–14, इश्यू–2।

12. प्रो0 लाल, एस0एन0 एवं डॉ0 लाल, एस0के0, भारतीय अर्थव्यवस्था : सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, 2021, शिव पब्लिशिंग हाउस, प्रयागराज, उ0प्र0।

13. फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीः द टार्गेट, मास्टरप्लान फॉर 5 इयर्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

14. फाइब वेज, इंडिया कैन क्रिएट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पोस्ट पैनडेमिक, 02 जून, 2021, ब्लूमबर्ग https://www.bloomberg.com/professional/insights/trading/five-ways-india-can-create-a-5-trillion-economy-post-pandemic/

15. मिश्र, ए0के0 एवं पुरी, वी0के0, भारतीय अर्थव्यवस्था, 2020, 32 वां संस्करण, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

16. रूरल इंडियाः रोड टू यू0एस0डी0 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बॉय 2025, पी–एच0डी0 रिसर्च ब्यूरो, पी–एच0डी0 चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री।

17. सोनी, स्वपनिल, कोविड–19 इम्पैक्ट पुसेज इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम 3 यीअर्स फॉरदर, 20 जुलाई, 2020 https://www.downtoearth.org.in/economy/covid-19-impact-pushes-india-s-5-trillion-dream-3-yrs-farther-72373